श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर : (क) जी हां।

(ख) यह परिषद् तीनों केन्द्रीय श्रमिक संगठनों द्वारा स्वयम् ही स्थापित की गई थी। सरकार को यह मालूम नहीं कि परिषद को एकत्रित लाने में किसी रुकावट का सामना करना पड़ा है।

(ग) से (घ) केन्द्रीय श्रमिक संगठनों में एकता और एक उद्योग के लिए एक यूनियन का सिद्धान्त, दो भिन्न विषय हैं। एक प्रतिष्ठान अथवा उद्योग में एक यूनियन को कानूनी मान्यता देने की योजना सरकार के विचाराधीन है। इस समय यह कहना संभव नहीं कि यह योजना कब तक क्रियान्वित की जायेगी :

ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन

689. श्री रामावतार शास्त्री क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रेड यूनियन एक्ट में संशोधन करने के लिए एक विधेयक का मसौदा तैयार किया है,

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य-मुख्य बातें क्या हैं, और

(ग) सरकार का उसे सभा में कब तक पेश करने का विचार है?

श्रम और पुनर्वास मंत्री (श्री आर० के० खाडिलकर) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औद्योगिक संबंधों के बारे में एक व्यापक विधेयक यथासीघ्र प्रस्तुत करने का प्रस्ताव है।

कच्चे माल की कमी के कारण बोकारो इस्पात संयंत्र को चालू करने में विलम्ब

690. श्री रामावतार शास्त्री : क्या इस्पात और खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पटना से प्रकाशित होने वाले अंग्रेजी दैनिक 'इंडियन नेशन' के 23 जून, 1972 के पृष्ठ 5 पर प्रकाशित समाचार की ओर उनका ध्यान दिलाया गया है कि कच्चे माल की कमी के कारण बोकारो इस्पात कारखाने के प्रथम चरण के चालू होने में विलम्ब होने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो कच्चे माल की कमी के क्या कारण हैं, और

(ग) इस कमी को पूरा करने के लिए सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

इस्पात और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जाहनबाज खान) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) बोकारो इस्पात कारखाने के लिए लोह खनिज, चूना पत्थर, मैंगनीज, कोयला आदि जैसे कच्चे माल की सप्लाई में मुख्यत यातायात की बाधाओं के कारण कुछ कमी हुई है। मंत्रालय द्वारा इस मामले में सभी संबंधितों के साथ लिखा-पढ़ी की गई है और अब सप्लाई में क्रमशः सुधार हो रहा है। फिर भी इस कारण से पहली धमन भट्टी को चालू करने में कोई देरी नहीं होगी।

खानों में निजी ठेकेदारी प्रणाली समाप्त करना

691. श्री रामावतार शास्त्री : क्या श्रम और पुनर्वास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या बिहार के विधायकों ने प्रधान मंत्री को एक ज्ञापन देकर खानों में निजी ठेकेदारी प्रणाली समाप्त करने की मांग की है;